भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2323

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना

2323. डॉ. सी. एम रमेश:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहाँ विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की संख्या सर्वाधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) द्वारा पीवीटीजी का उत्थान करने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) किस प्रकार एनआईईएसबीयूडी और आईआईई की सहायता कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करने में सहयोग कर रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में 500 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना किए जाने की योजना है और इस योजना की शुरुआत से अब तक कितनी जनजातीय महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य, जहां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की जनसंख्या 5,18,997 है, उन राज्यों में से है जहां पीवीटीजी की संख्या सबसे अधिक है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), मार्च 2024 से अपने स्वायत्त संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड) और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना-प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशलीकरण और उद्यमशीलता घटक को

कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में 18 राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों जिनमें पीवीटीजी की अच्छी खासी आबादी वाला आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है । यह योजना एमएसडीई सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है ।

मंत्रालय के प्रमुख उपायों में से एक वनधन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमशीलता विकास को सुविधाजनक बनाना है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं।

दिनांक 29.07.2025 तक, परियोजना के अंतर्गत 500 वीडीवीके में से कुल 405 वीडीवीके स्थापित किए जा चुके हैं और 37,161 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 31,560 महिलाएँ हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में, कुल 73 वीडीवीके के लक्ष्य में से 73 वीडीवीके स्थापित किए जा चुके हैं और 5,950 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 5,109 महिलाएँ हैं।

पीएम जनमन के अंतर्गत वीडीवीके के परिचालन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की, आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**कुल लक्ष्य वीडीवीके**	**परिचालित वीडीवीके**	**उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)**		**कुल ईडीपी**
				पुरुष	**महिला**	
1	आंध्र प्रदेश	73	73	841	5109	5950
2	छत्तीसगढ	16	16	39	2356	2395
3	गुजरात	21	21	751	299	1050
4	झारखंड	35	35	255	2567	2822
5	कर्नाटक	32	2	192	976	1168
6	केरल	5	5	269	156	425
7	मध्य प्रदेश	83	49	958	3245	4203
8	महाराष्ट्र	40	40	1776	1848	3624
9	ओडिशा	43	43	46	2279	2325
10	राजस्थान	50	50	0	8659	8659
11	तमिलनाडु	37	8	0	797	797
12	तेलंगाना	25	25	469	992	1461
13	उत्तर प्रदेश	5	3	0	266	266
14	उत्तराखंड	5	5	0	314	314
15	त्रिपुरा	30	30	5	1697	1702
	कुल	**500**	**405**	**5601**	**31560**	**37161**

****